उत्तर प्रदेश में उद्योगों पर प्रति व्यक्ति पूंजी विनियोजन

7066. **श्री मोलहू प्रसाद :**
श्री शिवचरण लाल :
श्री राम चरण :
श्री रामजी राम :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में उद्योगों का विकास कम होने का मुख्य कारण यह है कि केन्द्र ने वहां पिछली पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में अन्य राज्यों की अपेक्षा कम पूंजी लगाई है;

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगल तथा मद्रास राज्यों में उद्योगों पर क्रमशः प्रति व्यक्ति कितना पूंजी विनियोजन किया गया;

(ग) क्या सरकार का विचार चौथी पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश के लिये और अधिक सहायता देने का है ताकि पिछली योजनाओं में वहां लगाई गई कम पूंजी की कमी पूरी की जा सके; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

योजना, पैट्रोलियम तथा रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) और (ख). पहली तीन पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत, उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय औद्योगिक परियोजनाओं पर कुल विनियोजन 71 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो कि बिहार, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को छोड़कर अन्य राज्यों से सबसे अधिक है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा मद्रास राज्यों में केन्द्रीय उद्योगों पर प्रति व्यक्ति विनियोजन क्रमशः 10 रुपये, 40 रुपये और 22 रुपये था। योजना अवधि में उद्योगों में इस प्रकार पूंजी विनियोजन का निश्चय स्थान की अपेक्षा राष्ट्रीय आधार पर किया जाता है।

(ग) और (घ). चौथी योजना के अवधि के दौरान, उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय औद्योगिक परियोजनाओं पर अस्थायी अनुमानित विनियोजन 125.3 करोड़ रुपये है। राज्यों की चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये केन्द्रीय सहायता की राशि का निश्चय करने में सब सम्बन्धित विचारों को ध्यान में रखा गया था।

अनुसूचित बैंकों द्वारा उत्तर प्रदेश में पूंजी लगाई जाना

7067. **श्री मोलहू प्रसाद :**
श्री शिवचरण लाल :
श्री राम चरण :
श्री रामजी राम :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में राज्य स्तर पर कोई अनुसूचित बैंक नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान अनुसूचित बैंक इस राज्य में उस अनुपात में पूंजी नहीं लगाते हैं जिस अनुपात से उत्तर प्रदेश में उनमें धन जमा होता है;

(ग) यदि हां, तो क्या क्षेत्रीय तथा जिला बैंकों की स्थापना तथा विस्तार के लिये भारत के रिजर्व बैंक तथा भारत सरकार का विचार सक्रिय सहायता देने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) प्रश्न का